97

(Quantity in lakh tonnes)

	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Year	Imported	Exported
1990-91 .	12.73	0.15
1991-92 .	3.11	0.26
1992-93 .	5.79	0.37

(g) The details are as follows:-

	Quantity (in Kgs.)	
Country	Per Capita Pro- duction 1992	Per Capita Consumption 1984-86
India	14.61	14.0
China	5.48	3.6
Former USSR .	27.76	2.4
USA	4.79	3.1

Source : FAO Production Year Book 1992 and FAO Food Balance Sheet 1984-86.

मध्य प्रदेश में भारतीय खास निगम के गोदामों की भण्डारण क्षमता

4081. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या खाड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदाभों में खादान्नों के भण्डारण हेतु कुल कितनी क्षयता है ;
- (ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी माता में खाबाओं का भंडारण किया गया है और बादाओं की कितनी मास्रा खुले स्थान में पड़ी हुई ₹;
- (ग) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व में कुल कितने गोदाम हैं और इन गोदामों की कुल भंडारणं क्षप्रता कितनी है; और
- (घ) मारतीय खाद्य निगम को पूरे देश में कूल कितनी भंडारण क्षमता की और आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस योजना का प्रस्ताव है ?

7-8 RSS/ND/95

कार भंजालय के राज्य मंत्री (करपताथ राज) : (क) 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार भारतीय **बाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (हके हुए:और**

to Questions

कैंप) की कुल मंडारण क्षमता 234.58 लाख सीटरी टन है।

- (ख) 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार भार-तीय खाद निगम के ढके हुए गोदामों के कुल 158.35 लाख मीटरी टन और कैंप (खुले) स्थान में 26.85 लाख मी० टन खाद्याच भंडारित थे,।
- (ग) 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार मच्य प्रदेश में भारतीय श्वास निगम के पास कुल 152 गोदाम उपलब्ध हैं और 12.36 लाख मीटरी दन की भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप) उपलब्ध
- (घ) मैको स्तर पर, उपलब्ध स्टाक का भण्डारण करने के लिए वर्समाम भण्डारण क्षमता पर्याप्त है। तयापि, परिचालन अथवा प्रबन्धन संबंधी बाह्याओं के कारण अर्थाधक वसूली वाले क्षेत्रों, प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे कुछेक पाकेटों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों की अतिरिक्त भंडारण क्षयता किराये पर लेने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। भारतीय खाद्य निगम भी, जहां कहीं आवश्यकता सिद्ध हो जाती है, अतिरिक्त गंडारण क्षमता का निर्माण करता है। भारतीय खाद्य निगन की आठवीं योजना (1992---97) के दौरान 6.62 लाख मीटरी दन क्रमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

अंश्वोगिक लागत और मूल्य 🖷रीं की सिकारिशे

4082, श्रीमती चन्त्रिका अभिनंदन जैन : क्या खास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने चीनी का लेवी मूच्य निर्धारित इरने के प्रयोजन से महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों (जीन) में बांटने की महाराष्ट्र सरकार की भाग को "औद्यो-गिङ लागत और मुख्य ब्यूरो" कहे सौंप दिया है;
- (ख) क्या "श्रीहीमिक लागैत और मूल्य ब्यूरी" ने अपनी सिफारिशों प्रस्तुत कर दी हैं;
 - (ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और
 - (ब) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य शंतालय के राज्य मंत्री (भी कल्पनाय राय) : (क) और (ख) जी, हो।

(म) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) ने सिफारिश की यी कि दक्षिण महाराष्ट्र को दो केनों अर्थात् दक्षिण महाराष्ट्र